बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची के दीक्षान्त समारोह –2006 के अवसर पर महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति सैय्यद सिब्ते रज़ी का

<u>अध्यक्षीय भाषण</u>

आज के दीक्षान्त समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. मंगला राय, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, श्री सत्यानन्द भोक्ताजी, मंत्री कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, डा0एन0एन0सिंह, सीनेट, प्रबंध पर्षद तथा विद्वत् परिषद के सदस्यगण, विशिष्ट अतिथियों, डिग्री प्राप्त करनेवाले युवा वैज्ञानिकों, देवियों और सज्जनों।

झारखंड की जनता की ओर से, इस विश्वविद्यालय के अकादमिक समुदाय एवं छात्रों की ओर से तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, अपनी ओर से, मैं आप सबों का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह –2006 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे इस

बात की काफी खुशी है कि बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रहे झारखंड राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित वैज्ञानिकों, प्रसारकर्मियों, कृषक प्रतिनिधियों, नीति नियोजकों, विद्वानों और विद्यार्थियों की उपस्थिति में आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अध्यक्षीय सम्बोधन कर रहा हूँ और यह प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा0मंगला राय इस दीक्षान्त समारोह के मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित है।

आप सभी अवगत है कि लगभग 80 हजार हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल तथा करीब तीन करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश की सामाजिक–आर्थिक तथा कृषि–मौसम परिस्थितियाँ अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। पठारी कृषि तथा यहां के कृषक समुदाय, विशेषकर जनजातीय किसानों के हित साधन के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्‌घाटन 26 जून, 1981 को किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के मन में यहाँ के निवासीयों के लिए गहन प्रेम था और वह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देश का विकास करना है तो देश के दूर दराज के पिछड़े इलाकों का विकास करना होगा और इन पिछड़े इलाकों के विकास के लिए कृषि और उससे जुड़े हुये मत्स्य, दुग्ध, वानिकी आदि कार्यो पर हमें ध्यान देना होगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्व. कार्तिक उरांव द्वारा किये गये

प्रयासों को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। महान् देशभक्त तथा अदम्य साहस और ऊर्जा वाले जनजातीय नेता स्व. बिरसा मुण्डा जी, के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण होना उस महान् आत्मा के प्रति यहां की जनता की श्रद्धा का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं इन महान् विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ। बिरसा मुंडा जी ने केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, बल्कि आदिवासी समाज के विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों में हो रहे क्षरण के खिलाफ भी आवाज उठाई। यद्यपि हमें राजनीतिक आजादी मिल गयी तथा त्वरित विकास के उद्देश्य से नये राज्य का निर्माण भी हो गया, किन्तु बिरसा मुंडा जी के संकल्पों और सपनों को पूरा करने का दायित्व आज भी हमारे कंधों पर है। मनुष्य तथा प्रकृति और उसकी देन के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की जितनी जरूरत आज हो गयी है, उतनी पहले कभी नहीं थी।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा कार्यक्रम चलाता है। विश्वविद्यालय के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आधारभूत सुविधाओं तथा मानव संसाधन की कमी के बावजूद यहाँ के शिक्षकों और वैज्ञानिकों ने विभिन्न

कृषि गतिविधियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य सम्पन्न किये। इसके शैक्षिक प्रयासों का उद्देश्य योग्य स्नातक और स्नातकोत्तर कृषि विशेषज्ञ तैयार करना है, जो वर्षा आधारित कृषि की चुनौतियों का सामना कर सकें। अनुसंधान कार्यक्रमों का उद्देश्य मिट्टी एवं जल संरक्षण, बायो- डायवर्सिटी विकास, सहित वनों के संरक्षण तथा घरेलू पशुओं एवं पक्षियों के नस्ल सुधार द्वारा इंद्रधनुषी क्रांति लाना है। विश्वविद्यालय का प्रसार कार्यक्रम किसानों की सहभागिता से प्रौद्योगिकी प्रसार की नई तकनीक विकसित करने के लिए समर्पित है।

अपने अस्तित्व के 25 वर्षों में विश्वविद्यालय का कार्यकलाप प्रशंसनीय रहा है। गेहूँ, चावल, मडूआ सहित दलहनी, तेलहनी और सब्जी फसलों के कुल 37 उन्नत प्रभेद विश्वविद्यालय ने अबतक विकसित किए है। इसके अतिरिक्त एक फसली क्षेत्र को बहु फसली क्षेत्र में परिवर्तित करने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त फसल पद्धति और कृषि पद्धति से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी भी विकसित की गयी है। विश्वविद्यालय के पशुचिकित्सा संकाय को विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर सूअर और बकरी के नस्ल सुधार के लिए, राष्ट्रीय पहचान और पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

राज्य के 12 जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों और प्रसार पदाधिकारियों के लिए

बड़ी संख्या में गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ऑन–फार्म परीक्षण आयोजित करके विश्वविद्यालय ने नयी प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण की दिशा में Lab to land का महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने संस्था–ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम (आई.वी. एल.पी.) के अन्तर्गत अपने द्वारा तथा अन्य शोध संस्थानों द्वारा विकसित 70 प्रौद्योगिकी को परिष्कृत किया है, जिसे गांवों में अपनाया जा रहा है। इस प्रयास के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के वर्षा पर आश्रित Agri-ecosystem के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आई.वी.एल.पी. सेण्टर को सर्वोत्तम के रूप में पुरस्कृत किया गया है। देश में सर्वाधिक संख्या में देशज तकनीकी ज्ञान के संकलन, के लिए भी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। झारखंड़ में टिकाऊ कृषि विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में इस देशज तकनीकी ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य को अनाज और सब्जी फसलों के बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने हाल में महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को हजारीबाग जिले के गौरिया करमा में 800 हेक्टेयर का एक प्रक्षेत्र उपलब्ध कराया है, जहाँ प्रजनक बीज और

आधार बीज का उत्पादन किया जाएगा, जिसे प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों, बीज गुणन प्रक्षेत्रों तथा किसान उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्यरत 12 कृषि विज्ञान केन्द्रों ने समेकित कृषि विकास के लिए अपने-अपने जिलों में दो गांवों को अंगीकृत (Adopt) किया है। इससे अंगीकृत गांवों में अपेक्षित बदलाव आयेगा, जिसका प्रभाव धीरे-धीरे आसपास के गांवों में भी फैलेगा।

मुझे उम्मीद है, समय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और अधिक महत्वपूर्ण योगदान देंगे, विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि वानिकी, फल, फूल, सब्जी तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पादन, फल एवं सब्जी के परिरक्षण तथा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। इससे राज्य के गरीब किसानों को अपने सामाजिक-आर्थिक स्तर को उपर उठाने में पर्याप्त मदद मिलेगी।

मुझे विश्वास है कि समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. मंगला राय, जो अभी देश में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, भी इस बात को महसूस करेंगे कि इस विश्वविद्यालय को उनके प्रोत्साहन की जरूरत है। इसकी आधारभूत जरूरतों को केन्द्र सरकार तथा आई.सी.ए.आर. की उदार आर्थिक मदद की आवश्यकता है।

कहा जाता है झारखण्ड एक अमीर राज्य है, जहां गरीब लोग निवास करते हैं। यह सही भी है क्योंकि देश की लगभग 40 प्रतिशत खनिज सम्पदा यहां है और राज्य की 85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है, जो अपनी आजीविका के लिए प्रायः परम्परागत कृषि पद्धति पर निर्भर है। फसल उत्पादन, पशुपालन, वन–आधारित गतिविधियों तथा गृह उद्योगों जैसे कृषि उद्यमों में बहुत कम उत्पादन और लाभ होने के कारण राज्य में खाद्य एवं पोषण असुरक्षा है। हमारे राज्य के गरीब किसान अब भी प्राचीन कृषि तकनीक का व्यवहार कर रहे हैं तथा बेरोजगारी से त्रस्त ग्रामीण युवक अपने आपको चौराहे पर खड़ा महसूस कर रहे हैं। यहाँ उपलब्ध अपार प्राकृतिक संसाधनों तथा फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन एवं वन–आधारित उद्यमों से जुड़े अवसरों को देखते हुए नई कृषि तकनिकी के इस्तेमाल से राज्य में ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। बागवानी के क्षेत्र में फल, सब्जी, फूल, औषधीय एवं खुशबूदार पौधों का विशिष्ट महत्व है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सब्जी, मांस, मशरूम, शहद और वन–उत्पादों से जुड़ी असीम सम्भावनाएँ हैं। पशुपालन के क्षेत्र में बकरीपालन, सूअरपालन, भेड़पालन, मुर्गीपालन, बत्तखपालन एवं मछलीपालन से जुड़ी व्यापक सम्भावनाओं का दोहन किया जा सकता है। वन आधारित गतिविधियों में लाख, तसर तथा नॉन–टिम्बर

वन–उत्पादों का विशेष स्थान है। ग्रामीण शिल्प/घरेलू उद्योग के क्षेत्र में असुर, चिक बड़ाइक और महली जैसी कुछ जनजातियां अपने शिल्प कौशल के लिए जानी जाती हैं तथा कई कलाकृतियां और घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने में विशेषज्ञता रखती हैं। आज आवश्यकता है उपयुक्त प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप Technological intervention द्वारा उनमें ऊर्जा और उत्साह का संचार प्रवाहित करने की, ताकि इन उद्यमों को ज्यादा उत्पादक और लाभकारी बनाया जा सके।

मुझे खुशी है कि हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, तथापि झारखण्ड अपनी कुल वार्षिक आवश्यकता 20 लाख टन खाद्यान्न का लगभग 50 प्रतिशत भाग ही पैदा करता है। जबतक हम अपनी वर्त्तमान कृषि भूमि में औसत उत्पादकता को दुगुना नहीं करते तथा अतिरिक्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत नहीं लाते, तबतक इस कमी को पाटना संभव नहीं है। साथ ही, सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना होगा तथा प्रसार तंत्र को पुनर्गठित करना होगा। कृषि विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि शिक्षा पद्धति के ढांचे में भी बदलाव लाना होगा।

व्यावहारिक जैविक, भौतिक और सामाजिक विज्ञान की शुरूआत के साथ ही कृषि शिक्षा ने व्यावसायिक शिक्षा का दर्जा प्राप्त किया। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मान्य (डीम्ड) कृषि

विश्वविद्यालयों तथा देश भर में आई.सी.ए.आर. के संस्थानों की स्थापना के साथ ही कृषि शिक्षा को एक सुदृढ़ स्वरूप प्राप्त हुआ। समय के साथ–साथ कृषि विज्ञान को कृषि, बागवानी, पशुचिकित्सा, मत्स्यपालन, कृषि अभियंत्रण में विभक्त किया गया तथा गृह विज्ञान भी सहयोगी संकाय के रूप में रहा। वर्तमान शिक्षा पद्धति तथा देश के सरकारी अनुसंधान संस्थानों के नियोजन अवसरों ने कृषि को व्यावहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा है किन्तु अबतक यह विषय एक प्रोफेशन की व्यावहारिक संभावनाओं से कुछ दूर ही रहा है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं।

प्रथम, भारत में कृषि शिक्षा, फसल उत्पादन की ओर अभिमुख है तथा मूल्य संवर्धन की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

दूसरा कारण है कि कृषि शिक्षा, प्रौद्योगिकी प्रसार कार्य करने तक सिमटी रही किंतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग और कौशल को बढ़ाने जैसे पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जितना कि अपेक्षित है।

तीसरा, सरकारी अनुसंधान और प्रसार तंत्र से जुड़ी नियोजन संभावनाओं का ही प्रभुत्व कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में रहा है। वैज्ञानिक उप–विधाओं तथा प्रसार/संचार पद्धतियों पर ही ज्यादा जोर रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पर भी व्यावहारिक प्रबंधन के बजाय शोध पर ज्यादा जोर दिया जाता है। समय की पुकार है

कि कृषि शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों पर गंभीरता से विचार किया जाय तथा उसे नए संदर्भों में विकसित किया जाय, ताकि कृषि को एक विज्ञान के साथ–साथ एक प्रोफेशन के रूप में समुचित मान्यता मिल सके।

पठारी कृषि के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए आला दर्जे का दक्ष मानव संसाधन तैयार करने हेतु बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के समक्ष कृषि शिक्षा पद्धति को पुनःसंगठित करने का चुनौतीपूर्ण दायित्व है। मानव संसाधन विकास की दिशा में किए जाने वाले ऐसे प्रयास सुविचारित होने चाहिए, क्योंकि आनेवाले समय में किसी भी संस्थान का स्तर और ताकत उसके द्वारा तैयार किये गए मानव संसाधन के कौशल और दक्षता से आंकी जायगी, न कि संख्या से। इस दिशा में प्रथम प्रयास शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की मनःस्थिति में बदलाव लाने का होना चाहिए। विश्वविद्यालय को इस बड़ी चुनौती का सामना दृढ़ता से करना चाहिए तथा सुधार–आधारित रणनीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

वैश्वीकरण के इस दौर में किसानों को नये विकास के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए उत्पादकता बढ़ानी चाहिए तथा लागत को न्यूनतम रखते हुए गुणात्मक सुधार तथा मूल्य संवर्धन के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। वस्तुतः वर्तमान कृषि अनुसंधान पद्धति की सोच में मूलभूत बदलाव लाने की

आवश्यकता है। नयी सोच उस पुरानी सोच से निश्चित रूप से भिन्न होगी, जिसके तहत अनुशंसाओं का एक सेट विकसित करके किसानों को दिया जाता था और उन्हें (किसानों को) मात्र प्राप्तकर्त्ता समझा जाता था। इस सोच में निश्चित रूप से बदलाव आना चाहिए और तदनुरूप पाठ्यक्रम अनुसंधान में नयी चुनौतियों के मद्देनजर व्यापक कार्यक्रम पर आधारित अनुसंधान की ओर ध्यान देना चाहिए।

प्राथमिकता क्षेत्र

मेरे विचार से निजी/कारपोरेट/सहकारी क्षेत्र में प्रवेश के लिए कृषि स्नातकों को फूड प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी और परियोजना प्रबन्धन तकनीक सहित कृषि–व्यवसाय प्रबन्धन सिद्धान्तों को सीखना होगा। इसी प्रकार गैर–सरकारी संगठनों तथा किसानों/किसान संगठनों की सेवा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रसार एवं संचार कौशल, प्रशिक्षण तकनीक तथा प्रक्षेत्र प्रबन्धन दक्षता का घटक शामिल करना होगा। इसके अतिरिक्त झारखंड की कृषि के विकास के संदर्भ में इको–रीजनल एप्रोच, समेकित जल संसाधन प्रबंधन, समेकित पौधा पोषण प्रबन्धन, समेकित कीट प्रबन्धन, आर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग तथा कृषि पद्धति मोड़ में कृषि के विविधीकरण पर जोर देने की आवश्यकता है।

मैं आशा करता हूँ कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा पद्धति को पुनर्गठित करेगा, जिससे विज्ञान और प्रोफेशन दोनो में कृषि के स्वरूप में संतुलन आएगा तथा दोनों स्वरुप मिलकर कृषि उद्यम को राज्य और देश में ज्यादा उपयोगी और प्रति संवेदी बनायेंगे।

जैसा कि मैने पहले कहा झारखंड संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है । आवश्यता इस बात की है कि हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें और विकास कार्य करते समय, समाज के अन्तिम व्यक्ति की स्थिति में सुधार लाने का लक्ष्य रखें इस हेतु राज्य सरकार आई0सी0ए0आर0, विश्वविद्यालय तथा कृषकों के बीच आपसी सामंजस्य एवं सहयोग की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उपाधि और पुरस्कार प्राप्त करनेवाले युवा वैज्ञानिकों से अपील करूँगा कि वे साधन–विपन्न कृषक समुदाय की सेवा समर्पण, निष्ठा, संवेदनशीलता और समानुभूति के साथ करें। मैं सभी डिग्री प्राप्तकर्त्ताओं और उनके शिक्षकों को बधाई देता हूँ जिन्होंने दक्ष वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी तैयार करने में

महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण अकादमिक उपलब्धियों के लिए विशेष कर मैं कुलपति डा0एन0एन0सिंह और यहां के वैज्ञानिकों को पुनः बधाई देता हूँ, और आशा करता हुॅ कि देश और राज्य के सर्वांगीण विकास में आप सब अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे ।

जय हिन्द